समग्र विकास का सपना हो रहा साकार

रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखंड

विकास सतत चलनेवाली प्रक्रिया है. राज्य की सत्ता की जिम्मेदारी है कि वह राज्य के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी सलाह लेकर विकास की प्रक्रिया को पटरी पर लाये. झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से लगभग एक दशक तक विकास बाधित रहा. सभी वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप झारखंड को बनाने में लगातार बाधाएं आती रहीं. किसी भी राज्य का नेतृत्व राज्य की तमाम जनता की आकांक्षाओं को तभी पूरा कर सकता है, जब उसमें संवेदनशीलता हो तथा गरीब एवं वंचितों के प्रति स्वतः सहायता का भाव उसके मन में हो. राज्य का नेतृत्व करते हुए मैं खुद को गरीबों एवं वंचितों के साथ सहजता से इसलिए जोड़ पाता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी का दंश झेला है. मैं जानता हूं कि जब छोटी से छोटी आशा पूरी हो जाती है, तो एक गरीब की जिंदगी में किस किस्म का बदलाव आ जाता है. राज्य के आदिवासियों सहित हर घर, हर गांव को विकास से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है.

मैंने हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम समझा है. मैं मानता हूं कि राज्य की जनता की सेवा करना नेतृत्व का दायित्व है और इसमें किसी तरह की कोताही स्वीकार्य नहीं है. जनता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम जनोपयोगी योजनाएं होती हैं, जिन्हें गंभीरता से, ईमानदारीपूर्वक एवं जमीनी स्तर पर लागू कराना आवश्यक होता है, वर्ना अच्छी योजनाएं भी दम तोड़ देती हैं और जिनके लिए योजना लागू की गयी हैं, वे सरकारी प्रयास के बावजूद योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं. राज्य की सत्ता संभालने के बाद मैंने अधिकतर योजनाओं की मॉनिटरिंग खुद ही की है और लक्ष्य तय कर निश्चित समयावधि में योजनाओं को लक्षित समूह तक पहुंचाने की अनवरत कोशिश की है. आज से पांच साल पहले एक निराशा का माहौल था. युवा, महिलाएं, स्कूली बच्चे, बेरोजगार युवा, बुजुर्ग सभी में निराशा फैली हुई थी और लोगों के मन में नकारात्मक विचार घर कर गया था कि इस राज्य में अच्छा काम होना मुश्किल है. मुझे यह धारणा हर हाल में बदलनी थी. मैंने आम जनता से सीधे संवाद का रास्ता चुना, क्योंकि मेरा मानना है कि जिनके लिए योजनाएं बनायी जानी हैं, उनका सुझाव महत्वपूर्ण है. कई बार जमीनी स्तर पर समस्या की पड़ताल किये बिना ही योजनाएं तैयार हो जाती हैं, जिससे लाभुकों तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाता. यह प्रक्रिया मैंने राज्य के बजट निर्माण से ही शुरू की. हम जनता के बीच गये. गांव से लेकर प्रखंड और जिला से लेकर पंचायत तक आम जनता के बीच जाकर बैठे और जिलावार समस्याओं की सूची तैयार कर यह जाना कि आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आखिर जनता के किस कार्य में खर्च किया जाये. जनता ने जो समस्याएं बतायीं, उनके समाधान और सुझावों को हमने राज्य के आम बजट में शामिल किया और इसका सकारात्मक परिणाम मिला. कुछ योजनाएं मील का पत्थर साबित हुईं. राज्य की योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वयन में जनभागीदारी को साथ लेकर चल रहे हैं.

गोड्डा के सुंदरपहाड़ी में पोषण अभियान के तहत जागरूकता रथ को आदिवासी महिलाओं ने दिखायी हरी झंडी.

केंद्र की उज्ज्वला योजना को राज्य में भी गंभीरता से लागू करके लाखों महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलायी गयी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान का आह्वान किया और हमने राज्य में समय से पूर्व स्वच्छता एवं ओडीएफ का लक्ष्य हासिल कर लिया. इसी वर्ष से शुरू हुई मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रारूप देख कर राज्य के आम परिवारों में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब परिवार की बेटियों की पढ़ाई से लेकर विदाई तक का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है. इसके लिए वित्तीय मदद के जो प्रावधान किये गये हैं, उससे आम गरीब परिवारों को काफी हद तक चिंता से मुक्ति मिल गयी है.

हमारी सरकार ने इन पांच सालों में हर वर्ग का ख्याल रखा है. बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो या फिर महिला सशक्तीकरण, हर मोर्चे पर हमने सफलता के ऊंचे पायदान हासिल किये हैं. महिला शक्ति को राज्य की शक्ति बनाना है. दो लाख 16 हजार सखी मंडल के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है. एक नवंबर से सखी मंडल की बहनों को रेडी टू इट योजना से जोड़ दिया जायेगा. राजस्व गांवों में लग रही स्ट्रीट लाइट की देखरेख भी सखी मंडल की बहनों के जिम्में होगा. इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा. महिलाओं के नाम पर एक रुपये में जमीन की रजिस्ट्री का भी काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है. इससे महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ है. स्कूली बच्चों में ड्रॉपआउट कम करना, उनके मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ावा देना, बेंच-डेस्क, किताबों, पोशाक की व्यवस्था करना, दूर-दराज की बच्चियों के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था करना आदि कुछ ऐसे कदम रहे, जिनसे प्राथमिक शिक्षा में अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है. जहां तक शिक्षा का सवाल है, तो नये मेडिकल कॉलेज, तकनीकी विश्वविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कॉलेज खोलने से लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्रों की सीटें बढ़ाने जैसे कदम से उच्च शिक्षा अब पटरी पर आ गयी है. अटल क्लिनिक की शुरुआत कर हम कम खर्च में अपने मुहल्ले में ही समुचित इलाज की सुविधा प्रदान कर रहे हैं. इसका सीधा फायदा ज्यादातर गरीब लोगों को मिलेगा, जिनके लिए महंगी चिकित्सा एक सपना है. दूसरी ओर राज्य में आयुष्मान योजना के तहत भी रिकॉर्ड संख्या में मरीजों ने अपना इलाज कराया है. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली आपूर्ति, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, नागरिक सुविधाएं एवं परिवहन सुधार में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं.

पिछले पांच साल में वर्तमान सरकार ने 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई. पूरे राज्य में 59 ग्रिड सबस्टेशन और 200 सबस्टेशन का कार्य प्रगति पर है. राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद से इस दिशा में कोई विशेष कार्य हुआ ही नहीं था. इसी कारण बिजली की समस्या राज्य में उत्पन्न हुई थी, लेकिन ठीक इसके उलट वर्तमान सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आज बिजली की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है. इतना ही नहीं, पहाड़ों पर बसने वाले पहाड़िया और बिरहोरों तक बिजली पहुंचाई गयी है.

किसानों के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के बाद अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करनेवाले मजदूर और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से श्रम शक्ति अभियान की शुरुआत हुई. श्रम करने वाला हर व्यक्ति श्रमयोगी है. श्रमयोगी देश के अमूल्य निधि हैं. 25 सितंबर से दो अक्तूबर तक सभी प्रखंडों और शहरों में शिविर लगाकर श्रमिकों का निबंधन किया गया है. इस अभियान के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों- सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, ठेला चालक, खेतिहर मजदूर आदि के साथ-साथ भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करनेवाले श्रमिकों का निबंधन मुफ्त में किया गया है. मजदूरों का निबंधन कराने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि इन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण दिया जा सके.

हमारे प्रयासों से राज्य के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं का फायदा अब तेजी से मिलने लगा है. आगे भी हम लगातार आम जनता की सेवा में लगे रहेंगे.

जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण आदिवासी महिला से बातचीत भी की.